

09 मई 2024 : समाचार विश्लेषण

A. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

B. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

C. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी:

1. कैसे विडाल परीक्षण ने भारत की टाइफाइड समस्या की समझ को धूमिल कर दिया है:
2. भारत अब सौर ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है:

D. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 4 से संबंधित:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

E. संपादकीय:

राजव्यवस्था:

1. संवैधानिक टकराव सुलझाने का मौका:

F. प्रीलिम्स तथ्य:

1. 'अप्रैल में शाकाहारी भोजन की लागत 8% बढ़ी':
2. एस्ट्राजेनेका ने COVID-19 वैक्सीन वापस ले ली:

G. महत्वपूर्ण तथ्य:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

H. UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

I. UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

कैसे विडाल परीक्षण ने भारत की टाइफाइड समस्या की समझ को धूमिल कर दिया है:

विज्ञान और प्रौद्योगिकी:

विषय: विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकास, रोजमर्रा की जिंदगी में वैज्ञानिक विकास के अनुप्रयोग।

मुख्य परीक्षा: भारत में टाइफाइड के उपचार में चुनौतियाँ।

प्रसंग:

- टाइफाइड बुखार का सटीक निदान और प्रबंधन भारत में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है, मुख्य रूप से विडाल परीक्षण के व्यापक उपयोग के कारण।
- इसके प्रचलित उपयोग के बावजूद, परीक्षण की सीमाएं देश में टाइफाइड के वास्तविक बोझ को अस्पष्ट करती हैं, जिससे गलत निदान और अनुचित उपचार पद्धतियां परिणाम देखने को मिलती हैं।

विडाल टेस्ट से संबंधित मुद्दे:

- अशुद्धि और गलत व्याख्या: विडाल परीक्षण का हालांकि व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, लेकिन यह अक्सर गलत परिणाम देता है। एक एकल सकारात्मक या नकारात्मक रिपोर्ट विश्वसनीय रूप से टाइफाइड संक्रमण की पुष्टि या खंडन नहीं करती है, जिससे नैदानिक अस्पष्टता और संभावित दुर्व्यवहार होता है।
- मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण का अभाव: परीक्षण किट और प्रोटोकॉल में भिन्नता समस्या को बढ़ा देती है, विभिन्न निर्माता अलग-अलग कट-ऑफ मान और अभिकर्मकों को निर्दिष्ट करते हैं।
- मानकीकरण की यह कमी परीक्षण परिणामों की विश्वसनीयता और स्थिरता को कमजोर करती है।
- आर्थिक बोझ और एंटीबायोटिक दवाओं का अति प्रयोग: मरीज़, जो अक्सर परीक्षण की सीमाओं से अनजान होते हैं, परीक्षण और उसके बाद के उपचारों के लिए महत्वपूर्ण लागत वहन करते हैं। विडाल परीक्षण पर अत्यधिक निर्भरता अनावश्यक एंटीबायोटिक नुस्खों को बढ़ावा देती है, एवं रोगाणुरोधी प्रतिरोध ([antimicrobial resistance \(AMR\)](#)) को बढ़ाती है और रोगियों के वित्तीय तनाव को बढ़ाती है।

महत्व:

- टाइफाइड बुखार का कुप्रबंधन: गलत निदान और अनुचित उपचार नियम गंभीर जटिलताओं और घातक परिणामों का कारण बन सकते हैं, विशेष रूप से विलंबित या चूक निदान के मामलों में। विडाल परीक्षण पर व्यापक निर्भरता टाइफाइड के वास्तविक बोझ को अस्पष्ट करती है, जिससे प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप में बाधा आती है।
- रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) चिंताएँ: त्रुटिपूर्ण नैदानिक परीक्षणों के आधार पर एंटीबायोटिक दवाओं का अंधाधुंध उपयोग एएमआर में वृद्धि में योगदान देता है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। एएमआर से निपटने और एंटीबायोटिक उपचारों की प्रभावकारिता को बनाए रखने के लिए विडाल परीक्षण के दुरुपयोग को संबोधित करना महत्वपूर्ण है।

समाधान:

- वैकल्पिक निदान उपकरणों का विकास: प्रयासों को वैकल्पिक बिंदु-देखभाल निदान परीक्षणों पर शोध और कार्यान्वयन की दिशा में निर्देशित किया जाना चाहिए जो विडाल परीक्षण की तुलना में अधिक सटीकता और विश्वसनीयता प्रदान करते हैं। इन परीक्षणों में क्षेत्रीय विविधताओं पर विचार करना चाहिए तथा निदान और उपचार निर्णयों का मार्गदर्शन करने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास अनुमानों को शामिल करना चाहिए।
- उन्नत निगरानी और डेटा साझाकरण: एएमआर पैटर्न और टाइफाइड प्रसार की निगरानी के लिए निगरानी प्रणालियों में सुधार करना आवश्यक है। नमूना प्रसंस्करण और डेटा उत्पादन के लिए क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने से समय पर डेटा संग्रह और विश्लेषण की सुविधा मिल सकती है, साक्ष्य-आधारित हस्तक्षेप और उपचार प्रोटोकॉल की जानकारी मिल सकती है।
- निवारक उपायों पर ध्यान देना: स्वच्छ पानी, सुरक्षित भोजन प्रथाओं और स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने जैसी निवारक रणनीतियों पर जोर देना सर्वोपरि है। टाइफाइड संचरण के मूल कारणों को संबोधित करने से नैदानिक परीक्षणों पर निर्भरता कम हो सकती है और रोग का बोझ कम हो सकता है।

सारांश:

- भारत में विडाल परीक्षण का व्यापक उपयोग टाइफाइड के बोझ के सटीक आकलन को बाधित करता है और अनुचित उपचार प्रथाओं और एंटीबायोटिक के दुरुपयोग में योगदान देता है। विडाल परीक्षण की सीमाओं को संबोधित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें वैकल्पिक नैदानिक उपकरणों का विकास, उन्नत निगरानी प्रणाली और निवारक उपायों पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

भारत अब सौर ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है:

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी:

विषय: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में विकास, रोजमर्रा की जिंदगी में वैज्ञानिक विकास के अनुप्रयोग।

मुख्य परीक्षा: भारत में सौर ऊर्जा के उत्पादन की स्थिति।

प्रसंग:

- भारत वैश्विक सौर ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरा है, जिसने 2023 में जापान को पीछे छोड़ते हुए सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में तीसरा स्थान हासिल किया है। यह उपलब्धि अपने ऊर्जा मिश्रण के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, विशेष रूप से सौर ऊर्जा पर भारत की बढ़ती निर्भरता को रेखांकित करती है।

समस्याएँ:

- स्थापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन के बीच असमानता: भारत को अपनी स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता और वास्तव में उत्पादित बिजली के बीच पर्याप्त अंतर का सामना करना पड़ता है। इस अंतर को बिजली की मांग में उतार-चढ़ाव, परिचालन अक्षमताओं और ग्रिड एकीकरण में चुनौतियों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।
- आगे के मील के पत्थर को पार करने में चुनौतियाँ: हालाँकि भारत ने सौर ऊर्जा उत्पादन में जापान को पछाड़कर तीसरा स्थान हासिल कर लिया है, जबकि दूसरे सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य

अमेरिका को पीछे छोड़ना एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करता है। इस मील के पथर को हासिल करने के लिए सौर ऊर्जा उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि की आवश्यकता होगी, जिससे तकनीकी और टांचागत दोनों चुनौतियां सामने आएंगी।

महत्व:

- वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा परिदृश्य में योगदान: एक प्रमुख सौर ऊर्जा उत्पादक के रूप में भारत का उदय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर वैश्विक बदलाव में योगदान देता है। यह न केवल जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता से जुड़ी पर्यावरणीय चिंताओं को कम करता है बल्कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के अनुरूप भी है।
- आर्थिक अवसर और ऊर्जा सुरक्षा: भारत में सौर ऊर्जा बुनियादी ढांचे का विस्तार रोजगार के अवसर पैदा करके, स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देकर और आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि होती है।

समाधान:

- उन्नत ग्रिड अवसंरचना: स्थापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन के बीच अंतर को पाटने के लिए, भारत को मजबूत ग्रिड अवसंरचना में निवेश करने की आवश्यकता है जो सौर ऊर्जा उत्पादन में उतार-चढ़ाव को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने और इसे राष्ट्रीय ग्रिड में एकीकृत करने में सक्षम हो।
- ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों में निवेश: बैटरी जैसे ऊर्जा भंडारण समाधानों को तैनात करने से सौर ऊर्जा उत्पादन से जुड़ी रुक-रुक कर होने वाली समस्याओं को कम करने में मदद मिल सकती है, जिससे कम सौर विकिरण की अवधि के दौरान भी विश्वसनीय और लगातार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।
- नीति समर्थन और प्रोत्साहन: सौर ऊर्जा उत्पादन में निवेश को प्रोत्साहित करने और उद्योगों और घरों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को अपनाने की सुविधा के लिए नीतियों, सब्सिडी और प्रोत्साहनों के माध्यम से निरंतर सरकारी समर्थन महत्वपूर्ण है।

सारांश:

- भारत का सौर ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनने की ओर बढ़ना सतत विकास और नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। हालाँकि, स्थापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन के बीच अंतर को संबोधित करना एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है।

संपादकीय-द हिन्दू**संपादकीय:**

संवैधानिक टकराव सुलझाने का मौका:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

राज्यवस्था:

विषय: भारतीय संविधान-ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना।

मुख्य परीक्षा: मौलिक अधिकार बनाम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (डीपीएसपी)।

विवरण:

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ([Supreme Court of India](#)) के समक्ष प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में दो महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं।
- पहला प्रश्न संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) में "समुदाय के भौतिक संसाधन" शब्द की व्याख्या से संबंधित है।
- दूसरा प्रश्न यह बताता है कि क्या अनुच्छेद 39(बी) के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाए गए कानून समानता (अनुच्छेद 14) और स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19) के मौलिक अधिकारों ([fundamental rights](#)) पर आधारित चुनौतियों से प्रतिरक्षित हैं।

पृष्ठभूमि:

- भारतीय संविधान के भाग III और भाग IV के बीच टकराव उत्पन्न होता है। भाग III मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, जबकि भाग IV राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों ([Directive Principles of State Policy \(DPSP\)](#)) की रूपरेखा देता है, जो राज्य के प्राप्त करने योग्य लक्ष्य हैं।
- इन भागों के बीच तनाव संविधान की स्थापना के बाद से ही बना हुआ है और वर्षों से न्यायिक व्याख्या का विषय रहा है।

ऐतिहासिक संदर्भ:

- 1970 के दशक में कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा ([judicial review](#)) से छूट देने के उद्देश्य से संशोधनों के साथ संघर्ष तेज हो गया।
- 25वें संशोधन ने अनुच्छेद 31सी पेश किया, जो अनुच्छेद 14 और 19 के आधार पर विशिष्ट डीपीएसपी को लागू करने के लिए बनाए गए कानूनों को चुनौतियों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है।
- केशवानंद भारती मामले ([Kesavananda Bharati case](#)) ने इस सिद्धांत को स्थापित किया कि संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाले संशोधन अमान्य होंगे, जो आंशिक रूप से 25वें संशोधन को प्रभावित करेंगे।

बाद के घटनाक्रम और वर्तमान मुद्दे:

- 42वें संशोधन ([42nd amendment](#)) ने अनुच्छेद 31सी के दायरे का विस्तार किया, जिससे मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के बीच संबंध और जटिल हो गए।
- मिनर्वा मिल्स मामले ने शासन में मौलिक अधिकारों के महत्व पर जोर देते हुए 42वें संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया।
- हालाँकि, मिनर्वा मिल्स फैसले के बाद अनुच्छेद 31सी की स्थिति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

- संपत्ति मालिकों का मामला सर्वोच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद 31 सी के तहत अधिनियमित कानूनों की वैधता को स्पष्ट करने और मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के बीच संघर्ष को सुलझा लेने का अवसर प्रस्तुत करता है।

सारांश:

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य मामला मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच टकराव का सामना करता है, जिसमें अनुच्छेद 31सी के तहत बनाए गए कानूनों की वैधता पर स्पष्टीकरण का आग्रह किया गया है।

प्रीलिम्स तथ्य:**1. 'अप्रैल में शाकाहारी भोजन की लागत 8% बढ़ी':****प्रसंग:**

- क्रिसिल मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स के हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल में शाकाहारी भोजन की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो प्याज, टमाटर और आलू जैसे प्रमुख खाद्य पदार्थों में बढ़ती मुद्रास्फीति ([inflation](#)) की प्रवृत्ति को दर्शाता है।
- खाद्य पदार्थों की कीमतों में यह उछाल खाद्य मुद्रास्फीति में संभावित वृद्धि का संकेत देता है, जो परिवारों और नीति निर्माताओं के लिए समान रूप से चुनौतियां पेश करता है।

खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें:

- शाकाहारी भोजन की लागत: अप्रैल में घर पर बने शाकाहारी भोजन की लागत में साल-दर-साल 8% की वृद्धि हुई, जो पिछले महीनों की तुलना में तेजी को दर्शाती है।
- इस वृद्धि में योगदान देने वाले कारकों में प्याज, टमाटर और आलू जैसी आवश्यक सब्जियों की कीमतों में पर्याप्त वृद्धि शामिल है।

मुद्रास्फीति के रुझान:

- प्याज, टमाटर और आलू की कीमतों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई, साल-दर-साल मुद्रास्फीति दर क्रमशः 41%, 40% और 38% तक पहुंच गई।
- चावल और दालों में भी 14% और 20% की स्थिर मुद्रास्फीति दर देखी गई, जिससे समग्र खाद्य मुद्रास्फीति में योगदान हुआ।

आपूर्ति-पक्ष कारक:

- चावल, दालों और सब्जियों की कम आवक के साथ-साथ पश्चिम बंगाल में आलू की फसल को हुए नुकसान ने कीमतों में बढ़ोतरी में योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त, प्याज के लिए रबी रकबा कम होने से प्याज की आपूर्ति में और बाधा आई है, जिससे मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ गया है।

खाद्य मुद्रास्फीति पर प्रभाव:

- खुदरा मुद्रास्फीति के रुझान: 'रोटी चावल दर' रिपोर्ट आधिकारिक खुदरा मुद्रास्फीति डेटा से पहले खाद्य मुद्रास्फीति के रुझान के संकेतक के रूप में कार्य करती है। फरवरी और मार्च में भोजन की थाली की लागत में 7% की वृद्धि के बावजूद, खुदरा खाद्य मुद्रास्फीति क्रमशः 8.7% और 8.5% के उच्च स्तर पर रही।
- आधार प्रभाव और मूल्य गतिशीलता: पिछले वर्ष के निम्न आधार प्रभावों ने प्रमुख खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति दरों को बढ़ा दिया है। हालाँकि, जीरा, मिर्च और वनस्पति तेल जैसी कुछ वस्तुओं की कीमतों में गिरावट ने शाकाहारी थाली की कीमतों में वृद्धि की गति को आंशिक रूप से कम कर दिया है।
- मांसाहारी भोजन की लागत: अप्रैल में जहां मांसाहारी थालियों की कीमत में साल-दर-साल 4% की गिरावट आई, वहीं मार्च के स्तर की तुलना में 3% की वृद्धि देखी गई। बढ़ी हुई मांग और इनपुट लागत के कारण ब्रॉयलर की बढ़ती कीमतों ने मांसाहारी भोजन की लागत में इस वृद्धि में योगदान दिया है।

2. एस्ट्राजेनेका ने COVID-19 वैक्सीन वापस ले ली:

प्रसंग:

- यू.के. स्थित फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने अपने COVID-19 वैक्सीन की वैश्विक वापसी की घोषणा की है, जिसे भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सहयोग से 'कोविशील्ड' के रूप में वितरित किया गया था।
- एस्ट्राजेनेका का यह निर्णय कंपनी द्वारा टीके से जुड़े रक्त के थक्के जमने और प्लेटलेट काउंट में कमी से संबंधित दुर्लभ दुष्प्रभावों को स्वीकार करने के मद्देनजर आया है।

वापसी का कारण:

- दुर्लभ दुष्प्रभाव: एस्ट्राजेनेका के सीओवीआईडी -19 वैक्सीन को वापस लेने के फैसले को मुख्य रूप से दुर्लभ दुष्प्रभावों की पहचान के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, विशेष रूप से रक्त के थक्के और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के उदाहरण, जिन्होंने सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है।
- अद्यतन टीकों का अधिशेष: कंपनी महामारी की शुरुआत के बाद से विकसित किए गए अद्यतन COVID-19 टीकों की अधिशेष खुराक की उपलब्धता को वापसी के प्रमुख कारक के रूप में बताती है। अब कई वैक्सीन विकल्प उपलब्ध होने के कारण, एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन, जिसे यूरोप में वैक्सजेवरिया के नाम से जाना जाता है, की मांग में गिरावट आई है।

भारत में स्थिति:

- विनिर्माण रुका: भारत में एस्ट्राजेनेका के साझेदार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) ने दिसंबर 2021 से कोविशील्ड की अतिरिक्त खुराक का उत्पादन और आपूर्ति बंद कर दी है। यह निर्णय एस्ट्राजेनेका द्वारा शुरू की गई वैश्विक वापसी के अनुरूप है।
- दुष्प्रभावों पर पारदर्शिता: एसआईआई का दावा है कि उसने 2021 से वैक्सीन के साथ प्रदान किए गए पैकेजिंग इंsert में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम (टीटीएस) के साथ थ्रोम्बोसिस सहित सभी दुर्लभ से बहुत दुर्लभ दुष्प्रभावों का पारदर्शी रूप से खुलासा किया था।

अधिशेष उपलब्धता के निहितार्थ:

- मांग में गिरावट: अद्यतन COVID-19 टीकों की अधिशेष उपलब्धता के कारण एस्ट्राजेनेका के वैक्सजेवरिया की मांग में कमी आई है। नतीजतन, कंपनी ने वैश्विक स्तर पर वैक्सीन का निर्माण और आपूर्ति बंद कर दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. भारत में टाइफाइड बुखार के निदान के लिए किस परीक्षण के व्यापक उपयोग की प्रभावी रोग नियंत्रण में बाधा डालने के लिए आलोचना की गई है?

- (a) एलिसा परीक्षण
- (b) विडाल परीक्षण
- (c) रक्त कल्चर
- (d) मंटौक्स परीक्षण

उत्तर: b

व्याख्या:

- भारत में टाइफाइड बुखार के निदान के लिए विडाल परीक्षण की प्रभावी रोग नियंत्रण में बाधा डालने के लिए आलोचना की गई है।

प्रश्न 2. भारत के ऊर्जा क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- भारत 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया।
- भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि का श्रेय हाल के वर्षों में सौर पैनलों की लागत में उल्लेखनीय कमी को दिया जाता है।

3. भारत का लक्ष्य 2030 तक अपनी कुल बिजली उत्पादन क्षमता का 40% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से हासिल करना है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) उपरोक्त सभी

उत्तर: b

व्याख्या:

- कथन 1 गलत है। भारत ने 2023 में सौर ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को नहीं, बल्कि जापान को पीछे छोड़ दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका सौर ऊर्जा का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बना हुआ है।

प्रश्न 3. भारत की खाद्य कीमतों में हालिया रुझानों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. क्रिसिल मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स की एक रिपोर्ट अप्रैल 2024 में शाकाहारी भोजन की लागत में 8% की वृद्धि का संकेत देती है।
2. यह वृद्धि मुख्य रूप से दालों और पत्तेदार सब्जियों जैसी आवश्यक सब्जियों की कीमतों में उतार-चढ़ाव से प्रेरित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: a

व्याख्या:

- कथन 2 गलत है। रिपोर्ट में विशेष रूप से प्याज, टमाटर और आलू को मूल्य वृद्धि के प्रमुख चालकों के रूप में उल्लेख किया गया है, न कि दालों और पत्तेदार सब्जियों के रूप में।

प्रश्न 4. COVID-19 टीकों में हालिया घटनाक्रम के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. उभरते वेरिएंट के खिलाफ इसकी प्रभावकारिता के बारे में चिंताओं के कारण एस्ट्राजेनेका ने अपने COVID-19 वैक्सीन की वैश्विक वापसी शुरू कर दी है।
2. भारत में 'कोविशील्ड' के नाम से जाना जाने वाला टीका एस्ट्राजेनेका द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सहयोग से निर्मित किया गया था।
3. वापसी का निर्णय एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के संभावित दुष्प्रभावों के रूप में दुर्लभ रक्त के थक्कों और कम प्लेटलेट काउंट की रिपोर्ट के बाद लिया गया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) उपरोक्त सभी

उत्तर: b

व्याख्या:

- कथन 1 गलत है। COVID-19 टीकों की यह वापसी वेरिएंट के खिलाफ प्रभावकारिता के बारे में चिंताओं के कारण नहीं है।

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों के बीच संवैधानिक संघर्ष पर चर्चा कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक) (सामान्य अध्ययन - II, राजव्यवस्था) (Discuss the constitutional conflict between the Directive Principles of State Policy and the Fundamental Rights. (15 marks, 250 words) [GS-2, Polity])

प्रश्न 2. भारत हाल ही में सौर ऊर्जा का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है, जो देश के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत के ऊर्जा परिवर्तन के लिए प्रस्तुत चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा कीजिए। भारत अपनी वृद्धि को बनाए रखने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी स्थापित क्षमता और वास्तविक सौर ऊर्जा उत्पादन के बीच अंतर को कैसे पाट सकता है? (250 शब्द, 15 अंक) (सामान्य अध्ययन - III, पर्यावरण) (India recently became the world's third-largest producer of solar power, marking a significant milestone in the nation's renewable energy sector. Discuss the challenges and opportunities this presents for India's energy transition. How can India bridge the gap between its installed capacity and actual solar energy production to sustain its growth and ensure energy security? (15 marks, 250 words) [GS-3, Environment])

(नोट: मुख्य परीक्षा के अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों पर क्लिक कर के आप अपने उत्तर BYJU'S की वेब साइट पर अपलोड कर सकते हैं।)